से लगा कि यह सर्वे करीब-करीब पूरा हो गया है। उस पत्र में यह कहा गया था कि विश्व बैंक की मदद से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो आणविक ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात थी, उस दिशा में क्या प्रगति हुई है?

श्रीमती जयवंती मेहता: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने आणविक ऊर्जा के बारे में जो सवाल पूछा है, वह मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है बल्कि उसका संबंध परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से है। इसलिए इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि उस ऊर्जा स्रोत के बारे में हमारा मंत्रालय भी चिंतित है और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के साथ सहयोग करके हम परमाणु ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग बिजली निर्माण के कार्यों में अवश्य करेंगे।

सभापति महोदय, रैकिंग स्टडी के बारे में माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, मैं यह तो नहीं कह सकती कि उसकी पूरी रिपोर्ट बन चुकी है लेकिन अभी उस पर कार्य चल रहा है। उसके लिए विदेशी एजेंसियों का सहयोग लेने का प्रयास हम कर रहे हैं।

*603. [The questioner (Dr. Aladi P. Raj Kumar) was absent. For Answer *vide* page infra. 72]

MR. CHAIRMAN: Now Question No. 604. Shrimati Savita Sharda.

सूती धागे के निर्यात में कमी

*604. **श्रीमती सविता शारदा:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सूती धागे के निर्यात में काफी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार सूती धागे के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) सूती यार्न के निर्यात ने वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 के दौरान मात्रात्मक रूप से बढ़ोतरी के प्रवृत्ति दर्शाई है। तथापि, वर्ष 2001-2002 (अप्रैल–नवंबर) के दौरान सूती यार्न के निर्यात ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट की प्रवृत्ति दशाई है। अंतरर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की प्रवृत्ति के कारण इसमें

लगभग 8% की गिरावट आई है। सूती यार्न के निर्यात के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

वर्ष	(मिलियन कि०ग्रा० में) मात्रा
1998-99	376.86
1999-2000	443.99
2000-2001	505.49
2000-2001 (अप्रैल–नवंबर)	314.17
2001-2002 (अप्रैल–नवंबर)	288.75

सरकार द्वारा सूती यार्न के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:–

(1) शुल्क हकदारी पास-बुक (डी०ई०पी०बी०) की दर से 3% से बढ़ाकर 6% किया गया है।

(2) निर्यातक कताई एककों द्वारा निर्धारित खपत के लिए फर्नेस तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान की गई है।

(3) गैर-कोटा राष्ट्रों को सूती यार्न के निर्यात पर लगाई गई सभी सीमाओं तथा सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया है।

(4) कपास, सूती अपशिष्ट तथा सूती यार्न के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है, इससे इन निर्यातों को सभी प्रकार के प्रशासनिक नियंत्रणों से मुक्त किए जाने की अनुमति दी गई है।

(5) इस उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा दिनांक 1.4.99 से एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना आरंभ की गई जिसमें इस सुनिश्चित तरीके प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना के लिए नियुक्त किये गये वित्तीय संस्थानों से लिए गए वित्त पर 5% ब्याज की सब्सिडी प्रदान की गई है।

(6) सरकार द्वारा वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद् (टैक्सप्रोसिल) को सूती यार्न निर्यात आदि के लिए अपने बाजारों का विविधिकरण करने का परामर्श दिया गया है।

Decline in Export of Cotton Yarn

†*604. SHRIMATI SAVITA SHARDA : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the export of cotton yarn has declined considerably;

(b) if so, the steps Government propose to take to promote the export of cotton yarn; and

(c) if so, by when and if not the reasons therefore?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

For 8.5.2002 Regarding Decline in Export of Cotton Yarn

(a) to (c) The Cotton Yarn export in quantitative terms had shown an increasing trend during 1998-99, 1999-2000, 2000-2001. However, during the year 2001-02 (April-November) export of cotton yarn has shown a declining trend as compared to the same period of previous year. The decline of around 8% is due to recessionary trend in the international market. The details of Export of Cotton Yarn are given below :

(in Kgs. Mn.)

Year	Quantity
1998-1999	376.86
1999-2000	443.99
2000-2001	505.49
2000-2001 (Apr.—Nov.)	314-17
2001-2002 (Apr.—Nov.)	288.75

Government has taken various steps to increase the export of Cotton Yarn, which include:

(i) Duty Entitlement Pass Book (DEPB) rate has been increased from 3% to 6%.

†Original notice of the question was received in Hindi.

(ii) Duty free import of furnance oil has been allowed for captive consumption by the exporting spinning units.

(iii) All restriction on export of cotton yarn has been removed thus allowing the exports free from all administrative control.

(iv) Ceiling and all restrictions on export of cotton yarn to non-quota countries have been removed.

(v) To increase the competitiveness of the industry, Government has launched Technology Upgrading Fund Scheme. (TUFS) w.e.f. 1.4.99 where 5% interest subsidy is provided on the finance raised from the designated financial institution for projects of benchmarked technology upgradation.

(vi) Government has advised the Cotton Textile Export Promotion Council (TEXPROCIL) for diversifying its markets for cotton yarn export etc.

श्रीमती सविता शारदा : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने यहां जो आंकड़े दिए हैं वे नवंबर तक के हैं लेकिन दिसम्बर में भी 3 लाख, 69 हजार, साठ टन सूती धागों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले दिसम्बर में 4 करोड़, 10 लाख, तीस टन सूती धागों का निर्यात हुआ था। इस प्रकार इस दिसम्बर में पिछले दिसम्बर की तुलना में 9.92 प्रतिशत कम निर्यात हुआ है, जो कि चिंता का विषय है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव सूती धागों के निर्यातकों पर पड़ा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि सूती धागों के निर्यात में वृद्धि के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या सरकार सूती धागों के निर्यात में वृद्धि के लिए सूती धागों के उत्पादकों के माल को खरीदने पर विचार कर रही है ताकि उनके समक्ष जीवन-यापन की समस्या न उत्पन्न हो? क्या उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशेष योजना सरकार की तरफ से बनाई जा रही है?

श्री काशीराम राणा : सभापति जी, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, सूती धागों के निर्यात में पिछले साल थोड़ी गिरावट आई है। इससे पहले सूती धागे के निर्यात में कई बार 17 प्रतिशत और कई बार 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विश्व भर में यह जो रिसैशन का दौर चल रहा है, इसका प्रभाव सूती धागों के निर्यात पर भी पड़ा है और इसकी वजह से गत वर्ष सूती धागों के निर्यात में गिरावट आई है। लेकिन फिर भी सरकार ने निर्यातकों को और प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे उपाए किए हैं जिसका जिक्र मैंने रिप्लाई में भी किया है। जैसे कि अभी बजट में भी हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत

सारे ऐसे कदम घोषित किए हैं जिससे निर्यातकों का और प्रोत्साहन बढ़े। फरनेंस ऑयल के ऊपर पहले 20 परसेंट की डयूटी थी, वह डयूटी भी रद्द कर दी गई। निर्यात में जो भी रिस्ट्रक्शंस थे, वह भी हटा दिए गए हैं। जैसे कि एक से 40 काउंट का जो धागा था उसमें 500 मिलियन किलोग्राम तक की सीलिंग थी, उसको निकाल दिया है। जो धागा एक से सात काउंट का बनता था 20 मिलियन किलोग्राम की उसके ऊपर जो सीलिंग थी, वह भी हमने हटा दिया है। तो जो भी रिस्ट्रक्शंस थे, वह हमने हटा दिए हैं। इतना ही नहीं निर्यातकों को और प्रोत्साहित करने के लिए और खास करके सूती धागों के यूनिट और बढ़े हमने इनको और भी फंड देने के लिए कोशिश की है। जैसा कि टैक्सटाइल में टेक्नॉलोजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम के जरिए जो हम फंड देते हैं, उसका 29 प्रतिशत फंड सिर्फ स्पिनिंग यूनिट को गया है। 300 से ज्यादा हमें जो एप्लीकेशन मिली 3300 करोड़ रुपए परियोजना लागत की उसमें से माननीय सभापति महादेय जी, हमने 2400 करोड़ रुपए परियोजना लागत की एप्लीकेशन सैंक्शन कर दी हैं। हमने इसी तरह से निर्यात में जो रुकावट थी, वह खत्म कर दी है। इसके अलावा टी॰यू॰एफ॰ से भी उसको फंड मिले, उसके लिए हमने पूरा प्रावधान रखा है।

श्रीमती सविता शारदा : मंत्री महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न का अगला भाग है कि सरकार किन-किन देशों को सूती धागे का निर्यात कर रही है और किन-किन देशों में कितनी-कितनी मात्रा में सूती धागों की मांग कम हुई है? मैं सरकार से यह भी जानना चाहती हूं कि वस्त्र मंत्रालय के बहुचर्चित टी॰यू॰एफ॰ स्कीम स्पिनिंग सैक्टर पर भी लागू है? यदि हां, तो अभी तक इस स्कीम का स्पिनिंग सैक्टर पर क्या असर पड़ा है? मेरा दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है कि हमारे देश में कॉटन यार्न का प्रोडक्शन कितना है और वर्ल्ड मार्केट में हमारे कॉटन यार्न एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है? हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री काशीराम राणा : माननीय सभापति जी, हमारा जो सूती धागा एक्सपोर्ट होता है करीब 21 देशों से ज्यादा देश में हम निर्यात करते हैं और मैं अगर 2000-2001 की फिगर दूं तो करीब 5 लाख 54 हजार मीट्रिक टन का हमने निर्यात किया है जिसमें 6181 करोड़ का फारेन एक्सचेंज मिला। जहां तक यार्न प्रोडक्शन का सवाल है, सूती धागे का जो हमारा प्रोडक्शन है वह करीब 5 लाख मीट्रिक टन का है और जो पूरा यार्न है वह लगभग 9 लाख मीट्रिक टन का हमारा प्रोडक्शन है। सर, इसके सामने अगर देखा जाए तो जो हमारा इम्पोर्ट है वह इम्पोर्ट करीब एक लाख मीट्रिक टन का है। हमारा जो इम्पोर्ट है इससे 9 गुना है और इसमें भी अगर सूती धागे का निर्यात है तो हमारा निर्यात 5 गुना है। जैसा कि अभी सवाल हमारी माननीय सदस्या ने पूछा है, जो हमने निर्यातकों को

रिलेक्सेशन दिए, तो इससे क्या इम्पेक्ट पड़ा? सर, इम्पेक्ट यह है कि हमारे निर्यात और स्पिनिंग यूनिट के ऊपर यह असर हुआ है कि जो रिस्ट्रक्शन हटाए गए उससे एक नया कांफिडेंस उसमें पैदा हुआ है। जो कम्परेटिवली वर्ल्डवाइड रिसेशन था, इसका जो इफेक्ट होने वाला था, हमें लगता था कि इसका ज्यादा असर होगा। हम मानते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड शेयर है, सूती धागे के निर्यात में हमारा जो वर्ल्ड शेयर है, वह 25 प्रतिशत है हमें लगता था कि हमारा यह शेयर कम हो जायेगा और ओवरआल जो हमारे टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है, उसमें सूती धागे के एक्सपोर्ट का शेयर 12 परसेंट है। सर, इसके बारे में हम सोचते थे कि हमारी डबल डिज़िट में गिरावट आयेगी, लेकिन यह सिंगल डिजिट में सात से आठ प्रतिशत की गिरावट आई है। लेकिन मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि धागे के निर्यात में हमारी सिचुएशन इम्प्रूव होती जा रही है।

श्री दत्ता मेघे : सभापति महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के कारण एक्सपोर्ट में आठ प्रतिशत की गिरावट हुई है। आपको सूती मिलों की हालत मालूम हैं, निर्यात कम हुआ है, जितनी भी सूती मिलें हैं, चाहे वह महाराष्ट्र में हों, चाहे दूसरे प्रदेशों में हों, वे घाटे में चल रही हैं। हम लोग आयात ज्यादा कर रहे हैं और उसके ऊपर हमें जो टैक्स लगाना था, वह भी हमने नहीं लगाया है। इसलिए इसका प्रभाव किसानों पर पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर जो कापूसेका योजना थी, वह भी घाटे में चल रही है। हम निर्यात बढ़ायें और आयात कम करें और अगर आयात होता है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगायें, वर्तमान में जो नीति केन्द्र सरकार की है, उसके अनुसार क्या आप आयात पर ज्यादा टैक्स लगाने वाले हैं? निर्यात में जो गिरावट हुई है वह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मंदी के कारण नहीं हुई है, यह जो माल बनाते हैं गिरडी में सूत का, उसका उचित भाव नहीं आ रहा है, क्या यह बात सही है? यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री काशीराम राणा : सभापति महोदय, माननीय सांसद जी की बात थोड़ी-बहुत सही है। आज चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, वहां पर कई सूती धागे की मिलें बंद हुई हैं। सर, उसकी वजह यह है कि आज जो वैल्यु एडीशन रॉ-काटन के ऊपर हो रहा है। वह वैल्यु एडीशन की क्वालिटी छोटे-बड़े यूनिटों ने इस्तेमाल की, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए या अपने यूनिट का माडर्नाइजेशन करने के लिए, जो वह यूनिट अभी भी चलता है। जैसा मैंने पहले बताया कि 307 एप्लीकेशन यूनिट के आधुनिकीरण के लिए आईं और उसमें से 200 से ज्यादा यूनिट को हमने सैंक्शन किया है। हमारे यहां बी॰आई॰एफ॰आर॰ में जो यूनिट क्लोज-डाउन पड़ी हैं, उनमें 129 कॉटन मैनमेड फाइबर जो टैक्सटाइल्स यार्न की हैं, वे फरवरी, 2000 के अंत तक बी॰आई॰एफ॰आर॰ में हैं इसके साथ ही हमने 200 से ज्यादा नई यूनिट के लिए पैसे दिए, तथा नये यूनिट भी लगे हैं।

जो भी फैक्टरी या जो भी यूनिट माडर्नाइज हुआ या जिन्होंने अपनी क्वालिटी इम्प्रूव की, वे यूनिट अच्छी तरह से चलती हैं और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारा वर्ल्ड शेयर 25 परसेंट है, उसे बढ़ाने में भी हमें कामयाबी मिली है। जहां-जहां अपनी फैक्टरी, अपनी मिल और अपनी यूनिट को जिन्होंने माडर्नाइज किया है और माडर्नाइज के लिए भी टी॰यू॰एफ॰ में से हम उसको पैसा देते हैं और सबसे ज्यादा पैसा स्पीनिंग सैक्टर को गया है। मुझे लगता है कि इसका असर हो रहा है, आने वाले समय में उससे और इम्प्रूवमेंट होगा और हमारा निर्यात बढ़ेगा।

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मैं जल्दी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जब कॉटन यार्न का निर्यात घट रहा था तो आपने उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाये, उसमें जितने भी रेस्ट्रिक्शन्स कॉटन यार्न पर थे, वे सारे रेस्ट्रिक्शन्स आपने हटाये हैं, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कॉटन के एक्सपोर्ट पर, कपास के एक्सपोर्ट पर जो रेस्ट्रिक्शन्स हैं और जो कोटा आप अलग-अलग राज्यों को अलाट करते हैं, क्या उस कोटा अलाट करने की पॉलिसी में कोई परिवर्तन करके राज्यों को फ्रीहैंड दिया जा सकता है? राज्यों को पूरी तरह से मुक्ति दी जा सकती है कि आप जितना कॉटन यार्न एक्सपोर्ट करना चाहे, उतना करें?

श्री काशीराम राणा : सभापति महोदय, जहां तक रॉ-कॉटन के निर्यात का सवाल है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया है कोई भी स्टेट चाहे जितनी क्वांटिटी में ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम : कोटा तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। हमारा सवाल यह है कि जब कॉटन हम पैदा करते हैं तो आप हमें कोटा क्यों देते है? और हमें एक्सपोर्ट करने दीजिए।

श्री काशीराम राणा : सर, उसमें कोई कोटा नहीं है। मैंने कहा कि एक्सपोर्ट करने के लिए कोटा एक साल पहले था। उस समय हम कोटा अलॉट करते थे लेकिन अभी वह टोटली फ्री है। कोई भी स्टेट-चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो-कोई भी स्टेट रॉ-कॉटन एक्सपोर्ट कर सकता है और उसका जो इम्पोर्ट होता था, उसे रोकने के लिए कई स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से हमें कहा गया है कि उनकी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो तो हमने पांच प्रतिशत से दस प्रतिशत की वृद्धि की है और उसका असर यह हुआ कि लास्ट ईयर में जहां 22 लाख बेल्स का इम्पोर्ट हुआ, इस साल अब तक सिर्फ सात लाख बेल्स का इम्पोर्ट हुआ है। इससे हमारे फॉमर्स को जरूर लाभ पहुंचेगा।

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.